DESU, due to thefts and transmission losses in rupee terms during the last three years, year-wise and SEB-wise; and

(b) whether Government have examined the reasons for losses incurred by DESU annually, if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILA BEN CHIMANBHAI PATEL): (a) The details of the Transmission and Distribution losses inlcuidng thefts etc. incurred by various State Electricity Boards as well as DESU during the last three years are given in the Statement (*See* below)

(b) DESU is a wing of Municipal Corporation of Delhi, who will take appropriate steps for examining the reasons for losses incurred by DESU annually.

Statement

Loss of Revenue due to Transmission and Distribution Losses

Sl. No.	SEBs.	1990-91 Losses (Rs./Crs.)	1991-92 Losses (Rs./Crs.)	1992-93 Losses (Rs./Crs.)
1.	Andhra Pradesh	343.36	348.96	455.33
2	Bihar	132.16	146.94	176.94
3.	Gujarat	496.05	559.60	611.01
4.	Haryana	183.91	187.33	237.38
5.	Himachal Pradesh	39.82	36.70	46.90
6.	Karnataka	242.30	266.21	292.11
7.	Kerala	90.80	104.89	126.06
8.	Madhya Pradesh	451.39	558.58	646.72
9.	Maharashtra	767.75	623.34	873.79
10.	Orissa	132.29	132.47	157.78
11.	Punjab	189.09	206.31	259.00
12.	Rajasthana	288.74	285.80	391.59
13	Tamil Nadu	317.46	370.32	450.15
14.	Uttar Pradesh	575.56	620.30	801.58
15.	West Bengal	210.48	215.90	230.38
16.	Assam	55.94	48.88	50.84
17.	Meghalaya	2.67	3.86	4.86
18.	DESU	155.01(Prov.)	179.58(Prov.)	232.00 (Prov.)

Delay in clearance to Private Sector Companies in Power Sector

5385. SHRI G.Y. KRISHNAN: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Indian private sector power generation companies are still grouping in bureaucratic imbroglio when it comes to setting up fresh projects despite the deregulation in the policy;

(b) whether it is also a fact that the private companies have to go through an astounding 40 clearances in the Central Electricity Authority and at the State Government lavel;

(c) if so, what measures Government propose to take to remove all these impediments and to see that the system of one window clearance for all the private power sector companies is strictly enforced;

(d) whether the current annual ceiling of 1.5 billion on external commercial borrowings (ECB) for the power sector is considered too meagre to meet the sector's requirements; and

(e) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTER OF POWER (SHRIMATI URMILA BEN CHIMANBHAI PATEL): (a) and (b) No. Sir.

(c) Does not arise.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

मध्य प्रदेश से रूई का निर्यात

5386. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या वस्त्र मंत्री 16 अगस्त, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 2825 के किये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1994-95 के दौरान और चालू वर्ष में मध्य प्रदेश से कितनी रूई का निर्यात किया गया है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी): भारतीय कपास निगम ने अप्रेल, 94 मार्च, 95 के दौरान मध्य प्रदेश से कपास की 2250 गांठों का निर्यात किया।

सिले सिलाये वस्त्रों का निर्यात

5387. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:**
श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1995-96 के दौरान देश के विभिन्न राज्यों, विशेषकर गुजरात से सिले सिलाये वस्त्रों के निर्यात के लिए कोई सुनियोजित कार्यक्रम तैयार किया है और लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है और राज्य सरकार द्वारा क्या-क्या सुझाव दिये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी): (क) से (ग) वर्ष 1995-96 के लिए देश से सिले सिलाये परिधानों के निर्यात के लिए 4.8 बिलियन अमरीकी डालर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य-वार निर्यात लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते हैं और परिधानों के निर्यात के लिए राज्य-वार योजनाएं भी नहीं बनाई जाती हैं। तथापि, परिधानों के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है, जिसमें क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहन देना, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क पर पूंजीगत माल के निर्यात को सुकर बनाना, निर्यात उत्पादन के लिए कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात के लिए विशेष प्रबंध, निर्यात ऋण की बढ़ती हुई उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि शामिल है।

रूई की जमाखोरी

5388. **श्री गोपाल सिंह जी॰ सोलंकी:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में, विशेष रूप से गुजरात में, रूई की जमाखोरी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो कितनी रूई की जमाखोरी की गयी है; और

(ग) इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं और रूई के जमाखोरों के विरुद्ध क्या दांडिक कार्रवाई की गयी है या किये जाने का विचार है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी): जी, नहीं। इस समय इस प्रकार की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पटसन उद्योग के संबंध में प्रतिवेदन

5389. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री [illegible]:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उच्च स्तरीय प्राप्त समिति ने पटसन उद्योग के संबंध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति की मुख्य सिफारिशें कौन-कौन सी हैं;

(ग) उक्त समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं; और